III औद्योगिक शिथिलता और उसे दूर करने के उपाय

क. शिथिलता का निदान

30. हाल की औद्योगिक घटनाओं को अक्सर मंदी कह दिया जाता है । लेकिन इसका अर्थ औद्योगिक उत्पादन अथवा आर्थिक क्रियाकलाप में सामान्य रूप से कमी आना नहीं है । दरअसल औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि होती रही है । लेकिन वृद्धि के वार्षिक प्रतिशत की गति काफी धीमी हो रही है, जिसका मुख्य कारण कुछ उद्योगों में वृद्धि की गति का धीमा हो जाना या बिल्कुल कम हो जाना है । कई उद्योगों में वृद्धि की गति या तो कायम रही या बढ़ी है ।

31. 1960 से शुरू होने वाले दशक के पहले तीन वर्षों में औद्योगिक उत्पादन में 8 प्रतिशत के वार्षिक अनुपात से वृद्धि हुई है । उसके बाद से वृद्धि का अनुपात कम हो गया है ; 1965 में उत्पादन में 5.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई और 1966 में 2.6 प्रतिशत की तथा 1967 की पहली तीन तिमाहियों में 1.4 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि नहीं हुई ।

32. संलग्न रेखा-चित्र में, पिछले पांच राजस्व वर्षों में, तिमाहीवार, कुल उत्पादन के मौसमो के अनुसार समायोजित सूचक-अंक दिखाये गये हैं । रेखाचित्र में औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि के अनुपात में होने वाली कमी दिखायी गयी है ।

सारणी—3

उद्योगों में वृद्धि का स्वरूप

उद्योग	1956–64	पहले के वर्ष की तुलना में प्रतिशत वृद्धि		
	वृद्धि का वार्षिक औसत प्रतिशत अनुपात	1965	1966	1967 (जनवरी–सितम्बर)
बिजली की मशीनों से भिन्न मशीनें .	19.5	18.0	8.2	−0.4
बिजली उत्पादन . .	14.6	10.0	8.8	10.6
समाक्षारीय धातु . .	14.4	2.9	5.7	0.5
बिजली की मशीनें . .	13.5	13.4	8.7	16.5
रासायनिक पदार्थ . .	11.5	6.0	3.7	8.7

औद्योगिक उत्पादन के सूचक अंक

तिमाही औसत

1956 = 100

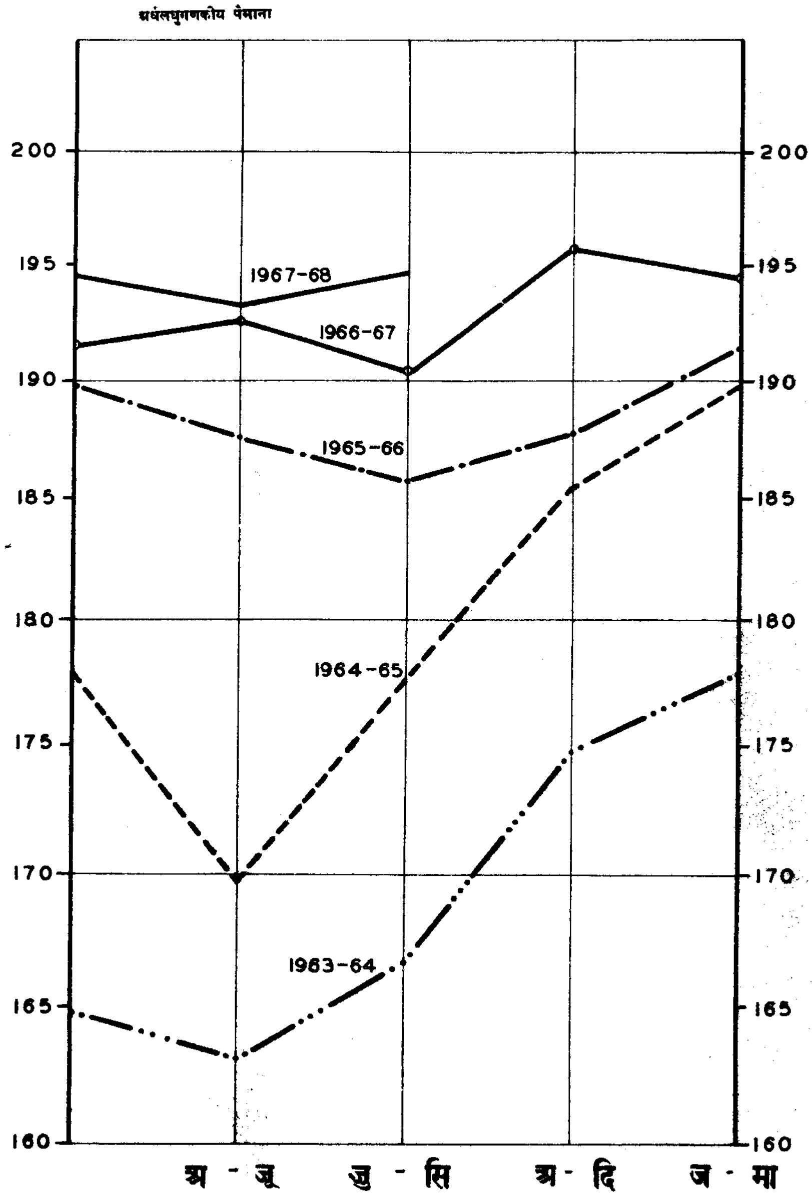

वित्त मंत्रालय, अर्थ प्रभाग

उद्योग	1956–64 वृद्धि का वार्षिक औसत प्रतिशत (अनुपात)	पहले के वर्ष की तुलना में प्रतिशत वृद्धि 1965	1966	(जनवरी-सितम्बर 1967
कागज और कागज से बनी वस्तुएं .	11.4	7.4	10.3	4.3
धातविक वस्तुएं . .	10.3	9.6	−7.6	−6.5
पेट्रोलियम से बनी वस्तुएं . .	10.2	6.6	23.8	24.6
धातु से भिन्न खनिजों से बनी वस्तुएं .	10.0	8.7	−1.0	1.5
जूते आदि (चमड़े के) . .	9.8	16.0	8.0	7.5
कृत्रिम रेशा . . .	9.8	3.2	−1.2	−0.4
लकड़ी और कार्क . .	9.5	14.4	−4.0	6.0
रबड़ की वस्तुएं . .	8.9	10.1	0.0	11.5
परिवहन के उपकरण . .	8.3	8.6	−9.2	−3.9
सामान्य सूचक-अंक . .	7.4	5.6	2.6	1.4
सिगरेट . . .	7.3	17.2	8.1	−6.6
खानों और पत्थर की खानों की खुदाई	6.8	9.0	3.3	2.0
ऊनी कपड़ा . . .	6.2	−15.5	−5.9	−4.4
चमड़ा . . .	4.2	1.2	−2.8	−1.5
खाद्य पदार्थों का परीक्षण . .	3.6	7.5	3.6	−18.0
सूती कपड़ा . . .	2.7	0.0	−2.8	−1.9
जूट की वस्तुएं . . .	2.4	4.0	−16.2	7.2

33. वृद्धि के क्रमिक ह्रास की प्रवृत्ति का प्रभाव उद्योगों पर समान रूप से नहीं पड़ा (सारणी 3 देखिये) । खाद्य पदार्थ परिष्करण (फूड प्रोसेसिंग), सूती कपड़ा और इंजीनियरी का सामान तैयार करने के उद्योगों में उत्पादन वृद्धि के लम्बे अरसे के रिकार्ड की तुलना में हाल के वर्षों में इन उद्योग-धन्धों के उत्पादन में भारी कमी हुई है । बहुत से दूसरे उद्योगों में उत्पादन की वृद्धि की गति कुछ ही धीमी रही । इस के बिल्कुल विपरीत, पैट्रोलियम की वस्तुएं और बिजली की मशीनें तैयार करने वाले उद्योग-धंधों के उत्पादन में इतनी वृद्धि हुई, जो उत्पादन-वृद्धि के उन के पहले के उल्लेखनीय रिकार्ड के मुकाबले भी काफी अधिक थी ।

34. उन वस्तुओं के उत्पादन में जिन्हें मोटे तौर पर उपभोक्ता वस्तुओं के अन्तर्गत वर्गीकृत किया जा सकता है, 1966 में 1 प्रतिशत से भी कम की वृद्धि हुई और उस के बाद जनवरी-सितम्बर 1967 में 6.5 प्रतिशत की कमी हो गयी । (परिशिष्ट की सारणी 1.12 देखिये) । इसी प्रकार, पूंजीगत माल

तैयार करने वाले उद्योग-धन्धों का उत्पादन, जो 1960 से शुरू होने वाले दशक के शुरू के वर्षों में तेजी से बढ़ रहा था, काफी घट गया और फिर उस में थोड़ी सी कमी हो गई। दूसरी ओर, मध्यवर्ती वस्तुओं के उत्पादन में, जो कुल औद्योगिक उत्पादन के एक-चौथाई से अधिक था, (जनवरी-सितम्बर) 1967 में लगभग 13 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

35. यद्यपि कुछ उद्योग-धंधों ने अपने उत्पादन की गति को धीमा कर के अपने को बाजार की स्थिति के अनुकूल बनाया, पर दूसरे उद्योगों की स्थिति ऐसी रही कि उन्हें योजनानुसार अपने उत्पादन का बोझ बर्दाश्त करते रहना पड़ा। अन्य उद्योगों, जैसे खनिज लोहे, कोयले, ढले लोहे, तैयार इस्पात और इस्पात की ढली वस्तुओं के मामले में उत्पादन की तुलना में स्टाक के अनुपात में वृद्धि हुई। हजामत बनाने के ब्लेडों, बाइसिकिलों और घड़ियों जैसी उपभोक्ता वस्तुएं बनाने वाले कुछ उद्योग-धंधों में भी ऐसी ही प्रवृत्ति रही (देखिये परिशिष्ट की सारणी 1.13)

36. औद्योगिक उत्पादन में जो शिथिलता आयी उसे केवल मांग के सामान्य स्तर का नीचा होना ही नहीं कहा जा सकता। पूर्ति की दिशा में प्रतिकूल प्रभाव आवश्यक आयातित वस्तुओं या देश में पैदा होने वाले कृषि पदार्थों की उपलब्धि में कमी होना—यदि अधिक नहीं तो उतना ही बड़ा कारण था।

37. औद्योगिक क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण भाग स्थानीय रूप से उपजाई जाने वाली कृषि वस्तुओं की सप्लाई पर निर्भर है। इन उद्योगों में सूती वस्त्र और जूट के वस्त्र बनाने वाले उद्योग और खाद्य पदार्थों का परिष्करण करने वाले उद्योग आदि शामिल हैं। साथ के चार्ट से पता चलता है कि कृषि पर आधारित इन उद्योगों के उत्पादन में 1966 के सारे वर्ष और 1967 की पहली छमाही में कमी हुई। उत्पादन में यह वास्तविक कमी 1965–66 और 1966–67 में व्यापक रूप से फसल खराब हो जाने के कारण वाणिज्यिक फसलों की उपलब्धि में कमी होने के कारण हुई। उपज की कमी को कुछ सीमा तक कपास और कच्चे जूट के आयात द्वारा पूरा किया गया (देखिये सारणी 4)। पूर्ति की प्रतिकूल स्थिति के परिणामस्वरूप न केवल वस्तुओं की वास्तविक कमी हो गयी, बल्कि कच्चे माल की लागत भी बढ़ गयी। औद्योगिक कच्चे माल के औसत मूल्य-स्तर में 1965–66 में 16 प्रतिशत की और 1966–67 में 21 प्रतिशत की अतिरिक्त वृद्धि हो गयी।

सारणी—4

उद्योगों के लिए आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धि[1]

	1964–65	1965-66	1966–67	1967–68
कपास (लाख गांठें)				
(सितम्बर–अगस्त)				
उत्पादन[5] . . .	60.0	56.1	56.0	62·7
आयात . . .	8.7	4.8	7.4	(उपलब्ध नहीं)
उपलब्धि . . .	93.7	84.9	84.8	तदेव

औद्योगिक उत्पादन का रूप

(परिवर्तित आधार : 1960=100)

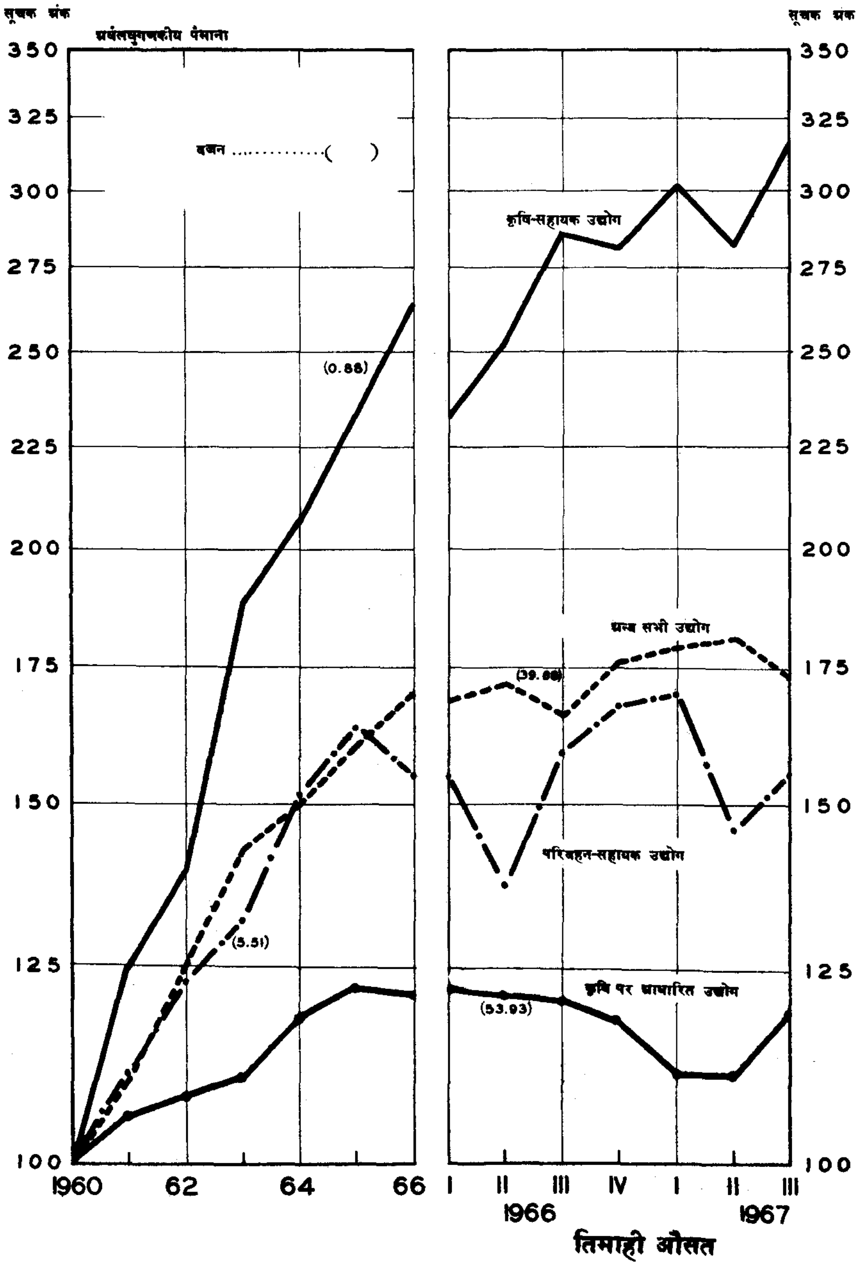

वित्त मंत्रालय, अर्थ प्रभाग

	1964–65	1965–66	1966–67	1967–68
कच्चा जूट[3] (लाख गांठें)				
(जुलाई-जून)				
उत्पादन . .	76.0	57.6	65.6	85.0
आयात . .	5.3	12.1	15.1	उपलब्ध नहीं
उपलब्धि . .	110.1	89.9	91.0	उपलब्ध नहीं
मुख्य तेलहन[2] (दस लाख मेट्रिक टन				
(जुलाई-जून)				
उत्पादन . .	10.5	8.0	8.3	10.5
गन्ना[4] (दस लाख मेट्रिक टन)				
(जुलाई-जून)				
उत्पादन . .	12.0	12.1	9.5	9.5

(1) उपलब्धि का अभिप्राय आयात और प्रारम्भिक स्टाक सहित उत्पादन से है

(2) मूंगफली, तोरिया और सरसों, तिल, अलसी, रेंड़ी और बिनौला

(3) मेस्ता सहित

(4) गुड़ के रूप में

(5) व्यापार के अनुमान

---

33. यद्यपि कृषि पर आधारित उद्योग-धंधे अधिकांशतः स्थानीय सामग्री पर निर्भर हैं, पर इंजीनियरी सम्बन्धी और रासायनिक पदार्थ बनाने वाले बहुत से उद्योग-धंधे बाहर से आने वाले कच्चे माल, हिस्सों और फालतू पुर्जों पर निर्भर हैं। कम विदेशी मुद्रा निर्धारित किये जाने से, आयात की जाने वाली इन वस्तुओं की सप्लाई 1965–66 में और उस के बाद के अधिकतर भाग में सीमित रही। उदाहरणार्थ विदेशों से मंगायी जाने वाली धातुओं और धातुओं से बनी वस्तुओं का मूल्य, जो 1960–61 में 40.5 करोड़ डालर था, 1965–66 में कम हो कर 38.8 करोड़ डालर और उस के बाद के वर्ष में 26.7 करोड़ डालर रह गया। यद्यपि बाद में 1966 में कच्चे माल, मशीनों के हिस्सों और फालतू पुर्जों के आयात को उदार बना दिया गया, पर वास्तव में इन का आयात कुछ समय के बाद हुआ।

39. फसल खराब होने से न केवल उद्योग-धंधों के काम आने वाली वस्तुओं की सप्लाई कम हो गयी बल्कि क्रय-शक्ति भी समाप्त हो गयी और निर्मित वस्तुओं की बिक्री का क्षेत्र भी सीमित हो गया। 1965–66 में कृषि-उत्पादन में 16 प्रतिशत की कमी से किसानों के बिक्री-योग्य फालतू (सर्प्लस) अन्न में और भी अधिक कमी हुई होगी। उसके बाद के वर्ष में खेती की पैदावार में थोड़ी और कमी हुई। बिक्री-योग्य अतिरिक्त माल में हुई अत्यधिक कमी का 1965–66 और 1966–67 में किसान की नकद आय पर जो प्रभाव पड़ा वह प्रति एकक (यूनिट) अधिक प्राप्ति होने के कारण कुछ सीमा तक प्रतिसंतुलित यानी बराबर हो गया। राष्ट्रीय आय के आंकड़ों के अनुसार किसान की प्रति एकक वसूली में 1965–66 में लगभग 13 प्रतिशत और फिर 1966–67 में 19 प्रतिशत की वृद्धि हुई। तथ्य और आंकड़ों के अभाव में, बिक्री-योग्य फालतू अन्न और किसान की नकद आय में होने वाले अन्तर का ठीक ठीक अनुमान नहीं लगाया जा सकता। पर इसमें शायद ही सन्देह की गुंजाइश हो कि किसान की निर्मित माल खरीदने की क्षमता 1965–66 में काफी कम हो गयी थी और सम्भवत: 1966–67 में इसमें पर्याप्त सुधार नहीं हुआ।

40. वस्तुओं के उत्पादन के सम्बन्ध में होने वाली प्रतिकूल घटनाओं से परिवहन सेवाओं की मांग, जो उत्पादन से प्रभावित होती है, कम हो गयी और इसका प्रभाव उन उद्योगों पर पड़ा जिन्हें "परिवहन सहायक" उद्योग कहा जा सकता है। इस समूह में आने वाले उद्योग–धंधों का––जिन में रेल के डिब्बे, ट्रक, टायर, ट्यूब आदि शामिल हैं––उत्पादन 1966 में लगभग 6 प्रतिशत कम हो गया (चार्ट देखिए)। रेल के डिब्बों का उत्पादन 1964–65 में 23,800 के उच्चतम स्तर तक पहुंच गया था, पर बाद में उसमें तेजी से गिरावट आयी। 1966–67 में केवल 15 हजार रेल डिब्बे तैयार किये गये और 1967–68 की पहली छमाही में वार्षिक उत्पादन की गति ग्यारह हजार रेल के डिब्बों से अधिक नहीं थी। इसी प्रकार, वाणिज्यिक मोटरगाड़ियों का उत्पादन 1964–65 में 36.9 हजार के उच्चतम स्तर तक पहुंच गया था, पर 1967–68 की पहली छमाही में इन गाड़ियों के वार्षिक उत्पादन की गति कम हो कर 25.6 हजार रह गयी।

41. पूंजी-निर्माण की प्रक्रिया में सामान्यत: जो शिथिलता आ रही थी वह परिवहन उपकरणों के उत्पादन की गिरावट का ही एक अंग थी। सरकारी क्षेत्र का पूंजी निवेश संबंधी व्यय, जो कुल राष्ट्रीय निवेश का लगभग 66 प्रतिशत था, दूसरी आयोजना और तीसरी आयोजना के आरम्भिक वर्षों में कुल विकास की गति को कायम नहीं रख सका। यद्यपि केन्द्रीय सरकार के बजट-साधनों से वित्त-पोषित कुल पूंजी निर्माण में (मौजूदा मूल्यों के अनुसार) 1962–63 में 20 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई और 1963–64 में लगभग 30 प्रतिशत की वृद्धि हुई, पर उसकी तुलना में बाद के वर्षों में यह वृद्धि क्रमश: 10 प्रतिशत, 7 प्रतिशत और 4 प्रतिशत ही रही। 1967–68 के बजट अनुमान से लगभग 8 प्रतिशत की वास्तविक कमी प्रकट होती है (**देखिए परिशिष्ट की सारणी 2.3**)।

42. सरकार के पूंजी निवेश में कमी करने की आवश्यकता लगातार सूखा पड़ने के कारण बजट में भारी असंतुलन हो जाने के कारण हुई (देखिये विभाग IV) सरकार के विभिन्न मंत्रालयों की ओर से पूर्ति और निपटान महानिदेशालय द्वारा की जाने वाली पूंजीगत वस्तुओं की खरीद में

1966–67 म 8 प्रतिशत से अधिक की कमी हुई। सरकारी खर्च की गति धीमी हो जाने से गैर-सरकारी क्षेत्र में विभिन्न उद्योग-धंधों का बाजार सीमित हो गया।

43. गैर-सरकारी निवेश का स्तर भी नीचा ही रहा। आयात किये जाने वाले उपकरणों का रुपयों में मूल्य बढ़ जाने, आने वाले वर्षों में मांग के सम्बन्ध में अनिश्चितता और प्रायोजना संबंधी सहायता की कम उपलब्धि के कारण गैर-सरकारी क्षेत्र में रुपया लगाने की क्षमता रखने वाले लोगों के मन में असमंजस की भावना पैदा हो गयी। सम्भव है कि कुछ उद्योगों की लाभदायकता में भी कमी हो गयी हो जिससे और अधिक पूंजी लगाने के लिए उपलब्ध आंतरिक साधनों में कमी हुई हो और नये पूंजी निवेश के लिए उत्साह ठण्डा पड़ गया हो। भारतीय रुपये का अवमूल्यन होने से पहले, कुछ मामलों में लाभ का स्तर ऊंचा रखा जा सकता था जिससे उत्पादन-क्षमता का काफी कम उपयोग किये जाने पर भी कुल लाभ की मात्रा काफी अधिक हो सकती थी। अवमूल्यन और आयात संबंधी शुल्क में घटबढ़ किये जाने के बाद लाभ की सीमा कम हो गयी। यद्यपि उद्योग-धंधों के लिए आयात की जाने वाली आवश्यक वस्तुओं की अधिक उपलब्धि से उत्पादन में वृद्धि करने और लाभ की सीमा कम होने पर भी लाभ का स्तर बनाये रखने के लिए आधार बन गया, पर मांग में कमी होने के कारण कुछ उद्योग-धंधे इस स्थिति का लाभ न उठा सके।

44. हालांकि आर्थिक क्षेत्र में निवेश की गति धीमी हो गयी, पर पूंजीगत वस्तुओं के निर्माण की औद्योगिक क्षमता बराबर बढ़ती रही। जिन प्रायोजनाओं का आयोजन 1960 से शुरू होने वाले दशक के पहले पहले के या बीच के वर्षों में किया गया था और जिनके सम्बन्ध में पिछले वर्षों में निर्माण-कार्य चल रहा था उनमें अब उत्पादन होने लगा। इनमें से बहुत सी योजनाएं पूंजीगत माल की मांग के संबंध में शीघ्रतापूर्ण विस्तार के परम्परागत अनुभव को प्रकट करने वाले अनुमानों पर आधारित थीं। चूंकि ये प्रायोजनाएं ऐसे समय में पूरी हुई जब पूंजी-निर्माण की गति धीमी थी, इसलिए उन्हें बिक्री संबंधी गम्भीर समस्याओं का सामना करना पड़ा। कुछ सीमा तक इस समस्या को उत्पादन-विविधता के उपायों द्वारा, उन वस्तुओं को, जो इस समय विदेशों से खरीदी जाती हैं, स्थानीय रूप से तैयार करके हल करने का लक्ष्य है।

45. उन क्षेत्रों में जहां मांग में वस्तुतः वृद्धि हुई, उत्पादन में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई। सरकारी और गैर-सरकारी निवेश में कमी हो जाने से कई प्रकार की इंजीनियरी संबंधी वस्तुओं की मांग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा, पर खेती के काम आने वाली मशीनों और उससे सम्बद्ध वस्तुओं के बाजार में काफी लचीलापन दिखायी दिया। उद्योगों के "कृषि सहायक उद्योग" नामक वर्ग के अन्तर्गत, जिसमें ट्रैक्टर, स्थिर (स्टेशनरी) डीज़ल इंजन, विद्युत शक्ति चालित पम्प और रासायनिक खाद तैयार करने वाले उद्योग आते हैं, पिछले दो वर्षों में विकास की गति बहुत तेज़ रही। 1965 में ट्रैक्टरों का उत्पादन 133 प्रतिशत, 1966 में 21 प्रतिशत और 1967 के पहले नौ महीनों में 38 प्रतिशत बढ़

गया । इससे सरकारी बजटों में, कृषि संबंधी कार्यक्रमों को दी गयी ऊंची प्राथमिकता प्रकट होती है । इस बात के भी सबूत हैं कि छोटे सिंचाई-कार्यों के काम आने वाले पम्पों और कृषि संबंधी अन्य उपकरणों में गैर-सरकारी निवेश का स्तर काफी ऊंचा है ।

ख. आर्थिक सुधार की नीतियां

46. जैसा कि बताया जा चुका है, औद्योगिक क्षेत्र विभिन्नताओं से परिपूर्ण था । वे उद्योग जिनका विकास तेजी से हुआ था और वे उद्योग जिनका उत्पादन बिल्कुल कम हो गया था दोनों एक ही स्तर पर आ गये । कुछ मामलों में पूर्ति यानी सम्भरण सम्बन्धी कठिनाइयां मुख्य थीं, जबकि अन्य मामलों में तैयार माल की मांग के साथ-साथ उत्पादन के लिए आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति में भी कमी हो गयी । कुछ अन्य मामलों में मांग की कमी, उत्पादन सम्बन्धी परिवर्तनों का निर्णायक कारण थी । अतएव ऐसे ही निदान के आधार पर इस शिथिलता यानी सुस्ती को दूर करने के लिए सरकारी नीति का निर्माण किया गया । इस नीति की मुख्य बातें ये थीं ।

(क) राजस्व और मुद्रा सम्बन्धी साधनों द्वारा सम्पूर्ण प्रभावी मांग पर बराबर नियंत्रण रखना;

(ख) सरकारी क्षेत्र द्वारा गैर-सरकारी फर्मों को पेशगी आर्डर देना;

(ग) उच्च प्राथमिकता वाली इंजीनियरी सम्बन्धी कुछ खास-खास वस्तुओं की देश में फिर से मांग पैदा करने के लिए ऋण देने के उपाय करना;

(घ) उद्योगों पर लगे नियंत्रणों को ढीला करना ताकि उन्हें बाजार की स्थिति के अनुसार उत्पादन के सम्बन्ध में परिवर्तन करने में आसानी हो; और

(ङ) देश में कुछ वस्तुओं की बिक्री में होने वाली कमी को पूरा करने के लिए निर्यात-प्रोत्साहन पर फिर से जोर देना ।

47. प्रतिबाहुल्यकारी (रिफ्लेश्नरी) नीतियों का कार्यक्षेत्र सीमित रहा । मुद्रा-बाहुल्यकारी बजट या ऋण सम्बन्धी नीति से अनाज और कम मात्रा में मिलने वाले कृषि पदार्थों की मांग में काफी वृद्धि हो जाती । चूंकि मुद्राबाहुल्य की आशंका वास्तव में मौजूद थी और विदेशी अदायगियों सम्बन्धी स्थिति पहले से ही कठिन थी, इसलिए कुल प्रभावी मांग के स्तर को बराबर नियंत्रण में रखना पड़ा ।

48. ऐसे नकद खर्चों को न बढ़ाकर जिनसे बजट सम्बन्धी घाटा ही बढ़ता है, सरकार ने सरकारी क्षेत्र के प्रतिष्ठानों की संकोचशील क्रय-नीति से उत्पन्न होने वाली अनिश्चितता के प्रतिकूल प्रभाव को रोकने का काफी प्रयत्न किया । रेलों और दूसरे सरकारी प्राधिकरणों को हिदायतें दी गयीं कि वे अगले राजस्व वर्ष में गैर-सरकारी फर्मों को पक्के आर्डर दें । इस प्रकार, रेल विभाग ने 1968–69 में रेलों के डिब्बे प्राप्त करने के अपने कार्यक्रम के अन्तर्गत 16,000 डिब्बों के लिए आर्डर दिये जबकि यातायात के प्रारम्भिक मूल्यांकन के अनुसार उक्त वर्ष की आवश्यकता केवल 10,000 नये डिब्बों की ही है । बोकारो के इस्पात तैयार करने के कारखाने ने 1.5 लाख मेट्रिक टन ढांचों के लिए टेण्डर मांगे । एयर इण्डिया इण्टरनेशनल ने कई प्रकार के उपकरणों के लिए कुल मिलाकर लगभग 14 लाख रुपये के मूल्य के आर्डर

दिये । हिन्दुस्तान टेलीप्रिण्टर्स लिमिटेड और इण्डियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज़ ने कुल मिलाकर 116 लाख रुपये के मूल्य के आर्डर दिये । अप्रैल–नवम्बर 1967 की अवधि में पूर्ति और निपटान महानिदेशालय ने विभिन्न सरकारी मंत्रालयों की ओर से कुल 262 करोड़ रुपये के आर्डर दिये जबकि 1966 की इसी अवधि में 237 करोड़ रुपये के मूल्य के आर्डर दिये गये थे ।

49. इसके अलावा, चुनी हुई वस्तुओं के आधार पर ऋण देने के उपायों द्वारा कुछ प्रकार की मशीनों और उपकरणों की देश में फिर से मांग पैदा करने या उसे बढ़ावा देने का प्रयत्न भी किया गया। औद्योगिक विकास बैंक ने पूंजीगत उपकरणों की विलम्बित अदायगी के आधार पर बिक्री की योजना की शर्तें नरम कर दीं । जिन लेनदेनों के लिए इस प्रकार के पुनर्वित्त की व्यवस्था की जाती है, उनमें से खेती के औजारों के लेनदेनों के लिए न्यूनतम रकम की शर्त उड़ा दी गयी और दूसरे मामलों में भी यह रकम और भी कम कर दी गयी, ताकि सहायता के क्षेत्र का विस्तार किया जा सके । जूट, सूती वस्त्र, चीनी, सीमेण्ट और कागज के उद्योगों के लिए संयंत्र तथा मशीनों, कीमती मशीनी औजारों और पूंजीगत किस्म के कृषि सम्बन्धी तथा सम्बद्ध उपकरणों की बिक्री के सम्बन्ध में, जिसके लिए पुनर्वित्त की व्यवस्था की जा सकती थी, विलम्बित अदायगी की अधिकतम सीमा सात वर्ष तक बढ़ा दी गयी । हुंडियों को फिर से भुनाने की दर 5 प्रतिशत निर्धारित की गयी और वित्तीय संस्थाओं के लिए यह आवश्यक कर दिया गया कि वे हुंडी को फिर से भुनाने की दर से 2 प्रतिशत से अधिक ब्याज न लें । सामान ढोने की मोटरगाड़ियों की मांग फिर से पैदा करने के प्रयत्न के रूप में, औद्योगिक विकास बैंक ने भी मोटर गाड़ियों के निर्माताओं या मंजूरशुदा किराया-खरीद कम्पनियों द्वारा, सड़कों पर माल ढोने वाली मोटरगाड़ियां चलाने वालों के हाथ मोटरगाड़ियां बेचने के लिए दिये गये ऋणों के लिए पुनर्वित्त की व्यवस्था करने की योजना शुरू की । हुंडियों को फिर से भुनाने की दर इस शर्त पर 6 प्रतिशत निर्धारित की गयी, कि वित्त व्यवस्था की मांग करने वाला बैंक 9 प्रतिशत से अधिक ब्याज न ले । निर्माताओं और किराया-खरीद की वित्त-व्यवस्था करने वाली कम्पनियों से भी आशा की गयी थी कि वे सड़कों पर माल ढोने वाली मोटरगाड़ियां चलाने वालों से सीधे $7\frac{1}{2}$ प्रतिशत से अधिक ब्याज न लें । रिजर्व बैंक ने घोषणा की कि किसी बैंक की वास्तविक भुगतान-क्षमता यानी उसकी नकदी या नकदी जैसी परिसम्पत्ति का हिसाब लगाते समय, वाणिज्यिक बैंकों द्वारा छोटे पैमाने के उद्योगों को दिये गये उन अतिरिक्त अग्रिमों की रकम हिसाब में नहीं ली जायगी, जिनकी गारंटी, ऋण गारंटी संगठन ने दी हो । निर्यात के लिए ऋणों के सम्बन्ध में दी गयी ऐसी ही तथा अन्य रियायतों के बारे में विभाग V में विचार किया गया है । देश में बनी मशीनों की बिक्री की विलम्बित अदायगी सम्बन्धी अपनी योजना के अन्तर्गत भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने 1967–68 की पहली तिमाही में 2 करोड़ रुपये से कुछ कम रकम के पुनर्वित्त की जो व्यवस्था की थी, तीसरी तिमाही में वह बढ़ कर 4 करोड़ रुपया हो गयी ।

50. औद्योगिक विकास तथा विनियमन अधिनियम (इण्डस्ट्रियल डेवलपमेण्ट ऐण्ड रेगुलेशन ऐक्ट) के उपबन्धों को पहले 1965 के मध्य में और दूसरी बार अक्टूबर 1966 में नरम बनाया गया, ताकि फर्में विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन कर सकें और इस प्रकार अपनी मौजूदा स्थापित क्षमता से और अधिक अच्छे ढंग से लाभ उठाकर अपने आप को बाजार की नई स्थिति के अनुसार ढाल सकें । नरम किये

गये उपबन्धों का क्षेत्र दिसम्बर 1967 में और बढ़ा दिया गया । सब से हाल की स्थिति यह है कि यदि कच्चे माल के अतिरिक्त आयात की आवश्यकता भी हो, तो भी उत्पादन-विविधता की दृष्टि से अनुमति दे दी जाती है, पर शर्त यह है कि तैयार की जाने वाली नयी चीज 1966 के मध्य में बनायी गयी प्राथमिकता सूची में सम्मिलित हो। यदि उत्पादन में विविधता लाने के लिए संतुलनकारी उपकरणों (बैलेंसिंग इक्विपमेण्ट) के आयात की आवश्यकता हो, तो उनके लिए विदेशी मुद्रा सम्बन्धी अनुमति-पत्र प्राप्त करना जरूरी है । सरकारी क्षेत्र की कई फर्में, खास तौर पर हेवी इलेक्ट्रिकल कारपोरेशन, अपने उत्पादनों में विविधता लाने के प्रस्तावों पर विचार कर रही है । हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड में स्वचालित मशीनें, ऐसी खरादें जिनसे उसी प्रकार की खरादें तैयार की जा सकें, कई प्रकार के औजार तैयार करने वाली खरादें आदि जैसे नये सूक्ष्म मशीनी औजारों का उत्पादन शुरू हो रहा है ।

51. सरकार की नीति मुख्यतः यह रही है कि जिन उद्योगों द्वारा तैयार की जाने वाली वस्तुओं की मांग देश में कम हो गयी है, लेकिन जिनके सम्बन्ध में सप्लाई की परिस्थितियां अनुकूल हैं, उन्हें अपना माल बाहर भेजने के लिए बढ़ावा दिया जाय । इस प्रकार विपणन सम्बन्धी उद्देश्यों के पुनर्निर्धारण से, अतिरिक्त क्षमता की अस्थायी समस्या और अन्तर्राष्ट्रीय मण्डियों में पैर जमाने की दीर्घकालीन समस्या को एक साथ हल करने में सहायता मिलेगी । ऋण देने के कई उपायों, नकद सहायता के क्षेत्र और उसकी दरों में परिवर्तन और प्रोत्साहन सम्बन्धी अन्य उपायों के द्वारा निर्यात अभियान को और भी शक्तिशाली बनाया गया ।

ग. नव-चेतना की सम्भावनाएं

52. जिस प्रकार लगातार सूखा पड़ने से मुख्यतः मांग और पूर्ति के सीमित हो जाने के कारण औद्योगिक उत्पादन की गति धीमी हो गयी थी, वैसे ही 1967–68 में कृषि-क्षेत्र में अनुकूल मौसम होने के कारण उद्योगों के विकास की गति में सुधार होने में सहायता मिलनी चाहिये । लेकिन इस सुधार की गति और इसका आकार दूसरी बातों पर भी निर्भर करेगा ।

53. जैसे-जैसे नयी फसल बाजार में आती जायगी, कृषि पर आधारित अधिकतर उद्योगों को माल सप्लाई करने की क्षमता में काफी सुधार होगा । उदाहरण के लिए, कपास के उत्पादन में 12 प्रतिशत और कच्चे जूट के उत्पादन में 29 प्रतिशत और तेलहन के उत्पादन में 26 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि होने की सम्भावना है । लेकिन इस सम्बन्ध में गन्ना एक अपवाद है, क्योंकि गन्ने की फसल कम होने की सम्भावना है, पर कुल मिलाकर कच्चे माल की समस्या हल होने लगेगी । पूर्ति के साथ-साथ कृषि पर आधारित उपभोक्ता वस्तुओं की मांग भी बढ़ने लगेगी । खेती से होने वाली आमदनी तेजी से बढ़ी है और अनुमान है कि कुल राष्ट्रीय आय में लगभग 11 प्रतिशत की या इतनी ही वृद्धि हो गयी है । जहां तक जूट उद्योग का सम्बन्ध है, अच्छी फसल और कच्चे माल की कम कीमतें निर्यात-प्रोत्साहन के जोरदार प्रयत्न के लिए उपयुक्त वातावरण तैयार करेंगी ।

54. बनास्पती के उत्पादन में, जिसमें 1966-67 में 8 प्रतिशत की कमी हो गयी थी, 1967-68 में सुधार हुआ और अप्रैल-नवम्बर 1967 में बनास्पती का उत्पादन पिछले वर्ष की इसी अवधि के

उत्पादन की तुलना में लगभग 10 प्रतिशत अधिक रहा। इसी प्रकार चाय और कहवे (काफी) की उपज में भी कुछ सुधार हुआ है। जान पड़ता है कि हाल में सूती धागे के उत्पादन में भी कुछ वृद्धि हुई है यद्यपि 1966-67 में सूती धागे का उत्पादन 1964-65 के उत्पादन की अपेक्षा 7 प्रतिशत कम था और 1967–68 की पहली छमाही में और भी कम हो गया था, लेकिन चालू राजस्व वर्ष की तीसरी तिमाही से कमी की यह गति बिल्कुल बदल गयी। अक्तूबर-दिसम्बर 1967 में सूती धागे का उत्पादन पहले के वर्ष के इन्हीं महीनों के उत्पादन की अपेक्षा कुछ अधिक रहा।

55. इंजीनियरी और रासायनिक उद्योगों की सप्लाई सम्बन्धी स्थिति भी अनुकूल है। इन उद्योगों की कई शाखाओं में अतिरिक्त क्षमता की काफी गुंजाइश है और आयात के लाइसेंसों की शर्तों को नरम बना देने के कारण मशीनों के हिस्सों और फालतू पुर्जों के आयात में काफी वृद्धि हुई है। अप्रैल-सितम्बर 1967 में धातुओं और धातुओं से बनी वस्तुओं का आयात 1966 के इन्हीं महीनों के आयात से 55 प्रतिशत अधिक था। इसी प्रकार 1967–68 की पहली छमाही में रासायनिक पदार्थों का आयात पहले के वर्ष के शुरू के महीनों के आयात की अपेक्षा 60 प्रतिशत अधिक था। उत्पादन में फिर से वृद्धि होने के चिह्न पहले से ही मौजूद हैं। उदाहरण के लिए ट्रकों को ही लीजिए, सितम्बर 1967 से ट्रकों की मांग के साथ-साथ उन के उत्पादन में भी वृद्धि हो गयी है और जनवरी-सितम्बर 1967 में 1966 के उत्पादन की तुलना में रासायनिक उद्योगों के उत्पादन की वृद्धि का अनुपात सामान्यतः काफी अधिक था। लेकिन इंजीनियरी और रासायनिक उद्योगों में नव-चेतना की गति, व्यवसायी वर्ग में आत्म-विश्वास के संचार, पूंजी निर्माण के स्तर और निर्यात में होने वाली प्रगति की सीमा के अनुपात में ही होगी। विदेशों में माल बेचना आसान न होगा, क्योंकि भारतीय उद्योगों का विकास ऐसी मण्डियों में हुआ है जो विदेशी प्रतियोगिता से सुरक्षित थीं। इस प्रकार आयात की जाने वाली बहुत सी वस्तुओं का स्थान देश में तैयार होने वाली वस्तुओं ने ले लिया है, लेकिन मूल्य और किस्म की दृष्टि से और अधिक सुधार की काफी गुंजाइश है। हाल में कुछ उद्योगों ने विदेशों में बिक्री बढ़ाने के काम में बड़ी दिलचस्पी दिखायी है। आने वाले वर्षों में यह दिलचस्पी बराबर बनी रहनी और बढ़ती रहनी चाहिए।